(c) Yes, Sir. It is a continuous process.

(d)To improve the quality of public address systems, microprocessor based announcement systems have already been provided on 111 stations and it is proposed to provide similar systems at other important stations progressively.

Opening of Dairy Industry for MNCs

1557. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether Government have opened Dairy Industry to MNCs, jeopardising the entire national milk grid, as reported in "The Financial Express", dated the 1st October, 1996;

(b) whether this has led to higher milk prices, increased adulteration and increased dairy imports; and

(c) if so, whether Government would consider reversing these anti-people policies?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Setting up of dairy plants in the country is subject to grant of registration by the registering authority, under the provisions of the Milk and Milk Product Order, 1992 issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. The registration is subject to, among other things, availability of marketable surplus in the proposed milkshed. All dairies whether set up by Indian companies or multinationals are governed by this order. This order provides for preferential treatment to the co-operatives.

(b) No Sir.

(c) Does not arise in view of answer to (a) & (b) above.

दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम

1558. श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1995-96 के दौरान देश में दूध का उत्पादन राष्ट्रीय मांग से लगभग 75 टन कम रहा;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई आपरेशन फ्लड स्कीम के बावजूद राष्ट्रीय मांग को पूरा नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि उपर्युक्त दोनों भागों का उत्तर "हां" है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय मांग को पूरा करने तथा उपर्युक्त योजना को पूर्णतया कारगर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के लिए दुग्ध उत्पादन के अंतरिम अनुमान के अनुसार दूध की आवश्यकता तथा उपलब्धता में अंतर लगभग 80 लाख टन का होता है, न कि 75 लाख टन का। तथापि, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम सहित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के कारण देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 1973-74 में 112 ग्राम से बढ़कर 1995-96 में 197 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई।

(ग) देश में दूध की मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित विभिन्न उपाय/योजनाएं आरंभ की गई हैं:-

1. **घरेलू संसाधनों से चुनिन्दा प्रजनन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के पशुओं की नस्लों का आनुवंशिक सुधार तथा अन्य चुने हुए क्षेत्रों में उन्नयन।**
2. **विदेशी डेयरी नस्लों के साथ गैर-प्रजातिय पशुओं का वर्ण-संकरण।**
3. **चुनिन्दा प्रजनन की महत्वपूर्ण भैंस नस्लों का आनुवंशिक सुधार तथा अन्य क्षेत्रों में गैर-प्रजातिय भैंसों का उन्नयन।**
4. **आहार तथा चारा संसाधनों का विकास।**
5. **उत्पादन कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य सेवा का आयोजन।**
6. **गैर-आपरेशन, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी विकास।**
7. **डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन।**

"Pollution Control Standards for Export Units"

1559. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have any responsibility to check the export units to satisfy domestic pollution control standards; and